लूटे गए यात्रियों को मुआवजा दिया जाए तथा रेल-यात्रा सुरक्षित बनाई जाये ।

(x) Reported notice for termination of services of some employees by the daily Maharashtra Herald of Ptona.

SHRI V. N. GADGIL: Sir, I want to make a statement under Rule 377.

The Daily Maharashtra Herald of Poona has given notice to 40 of its employees terminating their services on the ground that the firm running the newspaper has purchased new imported photo composing machine. It is reported that other newspapers like Sakal and Tarun Bharat in Poona and several other newspapers in the country are similarly going in for modern printing technology which will result in large scale unemployment in newspaper industry. It is also apprehended that introduction of machines like visual display Terminal, phototypesetter, composing|edit machines will do away with hot metal type production of composing and printing newspapers. At least in some cases, it is suspected that the big newspapers are going in for this kind of automation, with a view to avoid implementation of the Palekar Award. These big newspapers depend on the Government for newsprints, advertisements etc. and on nationalised banks for loans for buying such new machines. I request the Government to intervene in the matter and deny these facilities to them unless they agree to the principle of modernisation without hardship to the existing employees.

15.04 hrs.

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we come to the next item on discussion and voting on the Central Silk Board (Amendment) Bill, 1981.

Shri Shiv Kumar Singh has already taken six minutes. The balance left for this Bill is one hour and nine minutes. The Minister will reply at about 3-45 P.M. So, the speeches will conclude by that time. You may take one or two minutes more.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): There are a number of Members who want to participate on this. You will kindly extend the time by half-an-hour more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time has already been allotted. How can I alter it?

SHRI MOOL CHAND DAGA: You can alter it. The other bills are not important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You move an amendment.

Shri Shiv Kumar Singh.

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा): उपाध्यक्ष महोदय, कल इस बिल पर चर्चा करते हुए मैं निवेदन कर रहा था कि इस उद्योग में नए लोग नहीं आ रहे हैं । इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमारी पुरानी कलाओं को सीखने से नौजवान लोग थोड़ा घबराते हैं । यह उद्योग एक लेबर-इन्टेन्सिव इंडस्ट्री है और उसमें पूरे समय या आधे समय के लिए काफी काम लिया जा सकता है ।

इस उद्योग की यह भी कठिनाई है कि इसमें मास्टर वीवर्ज काफी आ गए हैं, जो पैसों के बल पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पावरलूम और हैंडलूम चलाने वाले एक्चुअल मजदूरों को अपने काम का पूरा लाभ नहीं मिलता है । इससे भी उन का उत्साह खत्म हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रैस-इन्फार्मेशन-ब्यूरो गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि :

"During the year 1977-78, Central Government sanctioned intensive Sericultural Development Schemes to be implemented as Central sche-

[ठाकुर शिव कुमार सिंह]

mes by the State Governments during the period 1977-78 and 1978-79 in the States of Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal and U.P. These schemes involving a total outlay of Rs. 4.4 crores have resulted in additional production 4.9 lakh kgs. of raw silk of the value of Rs. 13.5 crores and additional employment of one lakh persons. These schemes have been transferred to the respective State Governments with effect from 1st April, 1979".

इसके अनुसार सैंट्रल गवर्नमेंट ने एक ही साल में नए एक लाख लोगों को रोजगार का अवसर दिया है। इस प्रकार 4.5 करोड़ रु. का लाभ इस स्कीम के तहत मिला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लाभ केवल इने-गिने चारों राज्यों को जो परम्परागत सिल्कका उत्पादन करतों हैं, उनको मिलता है। आज हमारे देश में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, इन्दोर, उज्जैन, रायगढ़, चांपा-बिलासपुर, बस्तर आदि क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के इचलकरंजी, मालगांव, भिवण्डी, शोलापुर तथा इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बनारस, कानपुर, महुनाथभंजन, जहां पर पावरलूम और हैण्डलूम भी है तथा बिहार में भागलपुर, जहां पर इस उद्योग को पनपाने और चमकाने के लिए काफी नए क्षेत्र उपलब्ध हैं, परन्तु प्रचार की कमी के कारण आज हमारे देश के किसान इस काम को नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने कल निवेदन किया कि तमिलनाडु और कर्नाटक में कपास और अंगूर की खेती को खत्म करके उन्होंने सिल्क की खेती करना प्रारम्भ कर दिया है। वहां के किसानों को इससे काफी आय होने लगी है और वह अब इसकी फसल में रुचि लेने लगा है। जिस तरह से किसानों ने नई-नई वैराइटीज कॉटन की एच-4, वरलक्ष्मी, जे के एच-1 और 11 तथा ज्वार की शानदार खेती की, उसी तरह से यदि सिल्क में नई-नई वैराइटीज हों, तो वे सिल्क की भी शानदार खेती कर सकते हैं। इसी तरह से वे गन्ने और केले की भी दूसरी फसलों में रुचि ले रहे हैं। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी आपने कहा कि केवल दो मिन्ट की चर्चा की जाए, लेकिन बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको इस बिल पर बोलने के लिए अवसर दिया जाए। सिल्क की खेती को बढ़ा कर हम बहुत सा फारन एक्सचेंज उससे अरन कर सकते हैं।

सिल्क बोर्ड का आफिस, जो कि बम्बई में है, उसको बंगलौर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस को शिफ्ट करके साउथ ले जाया गया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान जो सिल्क का उत्पादन करते हैं, उनको बहुत परेशानी हो सकती है। यदि इसको शिफ्ट करना बहुत ही आवश्यक है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश, जो देश के मध्य में पड़ता है या फिर बनारस में जहां पर कि सिल्क काफी बनाई जाती है या बिहार के भागलपुर--ऐसे क्षेत्रों में इसका सैन्ट्रल आफिस शिफ्ट किया जाए या उसके जोनल आफिसेस बना दिए जाएं, जिससे कि सिल्क की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिल सके।

इसके साथ-साथ जैसा कि टैक्सटाइल की पोलिसी में कहा गया है कि नए स्पन मिल सापित किये जाएंगे मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान तीन स्पन मिल काम कर रहे हैं और तीनों एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। यदि इनको ठीक ढंग से चलाया जाए और तीनों शिफ्टों में काम किया जाए, तो हमारे देश में बहुत सा सिल्क यार्न बन सकता है। एग्रीकल्चर के सब-ग्रुप ने 260 करोड़ रुपये इस उद्योग को देने के लिए सिफारिश प्लानिंग कमीशन से की थी, लेकिन मझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस उद्योग को प्लानिंग कमीशन की ओर से 167 करोड़ रु. दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करते हुए, प्लानिंग कमीशन से कहना चाहता हूं कि इस उद्योग को बढ़ाने के लिए, फारेन-एक्सचेंज को प्राप्त करने के लिए इस में काफी संभावनायें हैं, क्षमताएं हैं, इसलिए इसको अधिक से अधिक पैसा दिया जाए। अभी हमारे ट्रेडिशनल बायर्स मलेशिया, हांग-कांग, एडिन

फिजि, आयर्लैंड और केनिया है और इसका मार्केट यू. एस. ए., वैस्ट-जर्मनी, स्वीटजरलैंड, इटली, कनाडा, साउथ-अरब, जापान आदि है, इन जगहों पर हमारा बहुत सा सिल्क भेजे जाने के चांसेस हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिल्क बोर्ड का जो अमेण्डिंग बिल लाया गया है उस में मेरे छोटे-छोटे पांच सुझाव हैं । मेरा पहला सुझाव यह है कि जो बिल लाया गया है उस की धारा 4 में आप जो अमेण्डमेन्ट लाये हैं वह इस प्रकार है--

"6(a) The Central Government may terminate appointment of the Chairman after giving him notice for a period of not less than three months:"

इस में कहा गया है कि चेअरमैन की सर्विसिज को टर्मिनेट करना है तो उस को तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये। मेरा कहना है कि यदि कोई आदमी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार करता है, पैसा खाता है या सिल्क बोर्ड का संचालन अपनी पूरी क्षमता से नहीं करता है तो उसे तीन महीने तक अवसर क्यों दिया जाए ? मेरी दृष्टि में ऐसे आदमी को रखने से पैसे की हानि होती है, उस को तीन महीने का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, उस को तत्काल डिस्मिस किया जाना चाहिये ।

2. मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सदस्य का जो तीन वर्ष का कार्यकाल रखा गया है इस में यह स्पष्ट नहीं है कि जो मेम्बर एक बार बन चुका है वह री-इलैक्ट होगा या नहीं होगा ।

3. तीसरा सुझाव--इस बोर्ड में केवल उड़ीसा, आसाम, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के सदस्य आते हैं, जब कि यू. पी. में बनारस, बिहार में भागलपुर और मध्य प्रदेश में रायगढ़, चांपा तथा विलासपुर में सिल्क का काफी उत्पादन होता है । इन प्रदेशों के प्रतिनिधियों को और खास कर किसानों को, इस बोर्ड में लिया जाना आवश्यक है ।

4. अभी हाल में कर्नाटक में ककून में पेस्ट का आक्रमण हो गया है, कीड़ा लग रहा है तथा धीरे-धीरे यह रोग आन्ध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जिस से सिल्क की पैदावार खराब हो रही है । एग्रीकल्चर विभाग तुरन्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे और फसलों का संरक्षण करे।

5. न केवल मेरी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों की यह भावना है कि जब से सिल्क बोर्ड बना है--1948 में यह अधिनियम पारित हुआ था और 1950 में यह बोर्ड बना था—तब से इस का चेअरमैन साउथ से आता है । सैन्ट्रल इन्डिया और नार्दन इण्डिया का भी इस में अवसर दिया जाय ताकि यह उद्योग एक सीमित क्षेत्र तक ही न रहे, इस का काम देश के किसानों को ही न रहे, इस का लाभ देश के किसानों को मिलें और देश में अधिक से अधिक

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of D.M.K., I wish to say a few words on the Central Silk Board Amendment Bill. The parent Act was passed in 1948 in which there was no provision stipulating the tenure of the office of Chairman and also no procedure had been enumerated therein for the removal of Chairman. All these 34 years the Central Silk Board had been functioning with this drawback and the Government had all along been helpless to terminate the services of Chairman who had not proved his worth. Now this deficiency is being sought to be removed by this amending Bill.

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri Era Mohan]

I can enumerate numerous instances to substantiate my contention that the Central Silk Board has not been functioning effectively all these years. The recent proof is that for the past three months the Board is literally non-existent. The orders shifting the Office of the Board from Bombay to Bangalore had been passed some three years ago. Since then the employees and the officials are on virtual strike. They do not want to go to Bangalore. All the work in the Board has come to a standstill. I wonder how the Government is putting up with this kind of wayward behaviour of the staff of the Board. Some three months more may be given to them for making up their mind. Even after that if they do not move out of Bombay, then all of them must be transferred to some other Central Government department and new staff must be posted in the Board and it should be shifted to Bangalore. In a vast country like ours, these decisions are taken in the interest of industry and those engaged in the industry. We should not allow the dangerous portends to gather roots in our country.

The very fact that now we are importing huge quantities of silk yarn from China is the proof positive for the Central Silk Board's callous neglect of the industry all these 34 years. When this could have been developed into a potential cottage industry, generating employment in the rural areas where crores and crores of people are unemployed, we are in the unfortunate situation of importing silk yarn. The price of imported silk yarn is much lower than that of indigenous yarn. That means China has taken great interest in developing this industry and the Chinese silk yarn has flooded our country. In fact this is proving a death-knell for the indigenous silk industry. The price of indigenous yarn cannot be brought to the level of imported Chinese yarn because of steep increase in input costs. Then there are many deficiencies in the system of distribution of the imported yarn. The genuine weavers are not getting silk yarn. In Tamil Nadu more than 10,000 families are dependent on silk yarn. They are all on the verge of losing their livelihood for want of adequate supplies of yarn. The hon. Minister should bestow his personal attention in this matter and ensure proper distribution of silk yarn.

Indian silk used to be a proud possession in foreign countries. We were the leading exporters of silk. Today we are gradually killing this industry by our importing silk yarn, by improper distribution of the imported yarn, and by not effective steps to augment silk yarn production. Even the master-weavers have become so disillusioned that they may call it a day. At this juncture, there is a rumour that the Government is thinking of constituting in a Silk Export Promotion Council. When there is no possibility at all for the export of silk, I wonder why should there be an Export Promotion Council. On the first day of this Session of Lok Sabha, there was a starred question about this and the hon. Minister replied in detail to all the supplementaries. We will be doing wrong by setting up this Export Council for silk. Instead, there is need for a Silk Development and Financing Council. Adequate funds are not available for the development of silk industry. The commercial banks do not extend loans. Similarly the nationalised Banks do not extend loans. There should be a financing institution at the highest level for this industry alone so that required financial assistance is given to the people engaged in the industry. I urge upon the hon. Minister not to take this suggestion casually. He must look into this and do the needful. He must order immediately the examination of the possibilities, and necessary steps must be taken in setting up this body.

Like Bangalore, many towns in Tamil Nadu have got salubrious climate for sericulture. Particularly Coimbatore is best suited for this purpose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Coimbatore is in your parliamentary constituency.

SHRI ERA MOHAN: Yes, Sir. I am very proud of that. When the Office of the Central Silk Board is set up in Bangalore, a regional office should be opened in Coimbatore so that necessary incentives are given to those interested in sericulture. Coimbatore is just like Bangalore in climatic conditions.

With these words, I support this amending Bill on behalf of my party, the D.M.K. and conclude my speech. I hope that the hon. Minister will pay attention to the suggestions I have made.

SHRI ZAINUL BASHER (Ghazipur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Bill has been brought forward in this House for a limited purpose. While supporting the Bill, I would like to make a submission to the hon. Minister who is doing his job very efficiently.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have got a certificate from him. The beginning itself is silken.

SHRI ZAINUL BASHER: I am giving him silken compliments. Sir, whenever we talk about silk, the name of Karnataka and Bangalore are always mentioned.

AN HON'BLE MEMBER: Mysore also.....

SHRI ZAINUL BASHER: Karnataka includes Mysore also. But, Sir, other places which are either producing silk or consuming silk and silk products are conveniently being forgotten. The reality is that Karnataka is not so important either in the production of silk or in the consumption of silk. I will give you figures in so far production of silk and silk products are concerned:—

Tasar Silk. 70% produced in Bihar and the balance in Maharashtra, Madhya Pradesh and Orissa.

Eri Silk . 80% produced in Assam and balance in Bihar and Orissa.

Muga Silk . 100% produced in Assam.

Mulberry Silk. 50% in Karnataka and balance in West Bengal, Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

So far as consumption of silk and silk products are concerned, the figure are as follows:

75% of Raw Silk output is consumed by weavers of Banaras, Bhagalpur and Malda.

Three places are consuming 70 per cent of silk. Eighty per cent silk handlooms are in U.P., Bihar, Assam, West Bengal, Madhya Pradesh and Orissa. And you are talking all the time about Bangalore, Karnataka whenever the question of silk comes up. On the top of it, the Central Silk Board always provides 70 per cent of its research, science, technological and extension strength to the State of Karnataka. Seventy per cent of the Central Silk Board budget is always earmarked for Karnataka at the cost of others.

Today, Karnataka sericulturist earns Rs. 10,000 per year from one acre of mulberry whereas lakhs and lakhs of adivasis in Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa and Assam hardly earn Rs. 500 per year by rearing Tasar silkworms. We owe more responsibility towards these underdogs to whom the 20-point programme is addressed.

There is a controversy about the location of the head office of the Central Silk Board about which my friend from Tamil Nadu was also talking. The head office of the Central Silk Board is being transferred from Bombay to Bangalore? Why? Karnataka is not such an important centre.

AN HON. MEMBER: It is because important M.Ps. are from there.

SHRI ZAINUL BASHER: An important MP from Assam is also there; Assam produces 100 per cent muga silk.

The head office should remain in Bombay.

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): But it is not working because of the controversy.

SHRI ZAINUL BASHER: There is a very strong lobby to shift the office from Bombay to Karnataka. I urge upon the hon. Minister to look into this matter. The head office of the Central Silk Board should be located at Bombay.

Now, I come to the zonal offices. There are some zonal offices situated at Srinagar, Bombay, Bangalore, Madras and Calcutta, but no zonal office is situated in Madhya Pradesh, Bihar, UP or in Assam, where more than 75 per cent silk is being consumed. I urge upon the Minister that at least a zonal office should be set up at Varanasi. Varanasi and its adjoining areas account for more than 50 per cent consumption in the country. One zonal office should also be situated at Bhagalpur, because sericulture has not been developed in those areas. In fact, it has not been allowed to develop in the areas, where the consumption of silk is more, because of certain vested interests. Sericulture should be developed in these areas; the climate is very suitable. In fact, everything else is suitable, but the encouragement is not being given, training is not being given, and consequently, sericulture is not being developed at places where the consumption is more.

Now, I come to the problems of Varanasi.

During the Winter Session, I raised a matter in this august House under Rule 377 that more than five lakh silk handloom weavers are out of jobs. The looms were closed because of the abnormally high prices of silk yarn. The prices increased by 50 per cent and the handloom weavers were out of the job. There was a strike in Banaras. It was not because silk was not available, but because the Silk Board or the other Agency of the Karnataka Government, which is responsible for the silk development and the sale of silk had so managed that some big people cornered the entire stock of silk and they raised the prices abnormally high. Since Banaras uses silk mostly from Karnataka and the prices went high to the extent of 50 per cent, there was the strike.

I am thankful to the Government. They have come to the rescue. They arranged some import from China and the other countries to meet the situation. Yet the situation remains the same. The reason is that the Varanasi sarees need certain grade of silk, but that has not been supplied to them. I have heard that the silk which is needed here in Varanasi has been supplied to Bhagalpur, which needs a different grade of silk. The U.P. Handloom Corporation has invested crores of rupees to buy the imported silk and the stock of the silk is piling at Varanasi, since it is not for the benefit of the weavers there. Therefore, I urge upon the Hon. Minister to kindly look into the matter and to arrange the supply in such a manner that the grade needed by the Varanasi Silk weavers is made available to them.

Sir, I am not against the South. I like South very much. I am rather devoted to South. But it so happens that the Central Silk Board is always dominated by the people of South, particularly of Karnataka. And they do not see the interests of the Northern States.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. George is from Karnataka.

SHRI ZAINUL BASHER: Yes, both the Fernandes are from Karnataka. But he is moving round the country and you are stuck there.

Therefore, I urge upon the Hon. Minister to kindly see to it that when the Board is constituted, different parts of the country which produce silk or consume silk are also represented on it. And the Hon. Minister should at least ensure that the Chairman on the Board should be from the silk consuming area. I am not offering myself, but anybody from the silk consuming area. must be appointed Chairman on the Board.

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): Sir, I came from Karnataka which supplies the bulk of raw silk. Furthermore, I represent a constituency which is the nerve centre for silk trade.

Sir, I cannot understand why my Hon. friends have started this controversy. From time immemorial Karnataka has been producing almost all the raw silk required by the whole of the country. Of late, Tamil Nadu has taken steps to see that it also has good production of raw silk production. But I am not so narrow-minded as some of my friends are. I would say that the Silk Board should be situated in a State which has the highest silk production and the highest quantum of trade. Tamil Nadu is also near Karnataka States, and I would request my Hon. friend from Tamil Nadu, let us not quarrel so that it is sent to Kashmir.

Sir, Bangalore is a place where its main industry is situated and it is the biggest market in the world. Furthermore, there are a large number silk weavers working in Bangalore. Therefore, I humbly appeal to the Government and my hon. friends to see that it should be located in Karnataka for the present. And when the silk industry spreads and other States come forward to produce more of silk, then they can ask for it. But let them not do anything in a hurry, because industry is already suffering. And I don't want this industry to further suffer by premature transfer from Bangalore to some other place. Bombay is neither a silk producing area, nor has it got silk industry. So, I don't understand why there is such a cry to take the Silk Board away to Bombay.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is this part of the speech, the Minister will find very difficult to reply. He is supporting Bombay and you are supporting Bangalore.

SHRI T. R. SHAMANNA: Sir, this Act should have been amended long ago.

The Silk Board has not helped much to the silk trade and the silk industry. Nor has it done anything for its development or for its research work. Last year the silk production was affected because of the destruction of the silk crop by the Hoozi fly. Therefore, the silk industry had to suffer a lot and the silk prices were fantastically high at that time. The Silk Board had not come up with any remedy to overcome or avoid the havoc caused by the Hoozi flies. Therefore, I charge the Silk Board for having been completely unhelpful as far as the development of the silk industry is concerned. The job of the Silk Board is to see that research is made so that we may be able to have quality silk at a lesser cost.

The Silk Board as it has been constituted now, is to be scrapped. I recommend that the Board must be constituted on the pattern of the Coffee Board where the interests of all the people connected with the silk industry are taken on it. The Silk Board should also see that the industry as a whole develops properly and that these engaged in this industry benefit economically. I am dare say that silk industry can give employment to lakhs of people. In the same way it can help a great deal in earning a lot of foreign exchange through foreign trade also. Therefore, the Silk Board has to be rejuvenated on proper lines, to see that the silk industry develops on right lines. The silk industry can solve the unemployment problem to a great extent. Furthermore, it will fetch foreign exchange if we export silk.

The silk industry is a very important industry. Once I was the Chairman of the Central Beggar Relief Committee. In order to see that the beggars were given some employment, we engaged some beggar boys and engaged them on silk twisting. We were paying them Rs. 2 per day. After receiving training, these boys were taken by the silk twisting factories where they were paid Rs. 12 to Rs. 14 a day.

[Shri T. R. Shamanna]

There is ample scope in the country for the silk industry to develop. World Bank has given a large sum for silk development. It may be expended on the silk industry.

It is unfortunate that the Silk Board and the Karnataka Government have not taken proper steps. They have made a mess of the whole thing. Silk which was selling at Rs. 250 a Kg. went up to Rs. 720 per Kg. not only in Karnataka, but also in Tamil Nadu. The weavers were put to great hardships—in Kancheepuram in Tamil Nadu, Dharmavaram in Andhra, Banaras in U.P. and in Kashmir. The weavers suffered very much on account of the high cost of raw silk. The weavers' plight was miserable.

I have raised this matter in Parliament under rule 377, interpollations and Calling Attention. But nothing has been done.

There is now a crash in the market, in respect of silk. The State Government of Karnataka, instead of taking measures to allevite the sufferings of weavers, have formed a Silk Exchange which consists of vested interests. So, they went on raising silk price, and they have now stored about Rs. one crore worth of raw silk. Four months back, the price was ranging between Rs. 600 and Rs. 720. Now it has come down to Rs. 350. This has hit the silk weavers of different States. I am quite sure that because of this fall in prices, many people in the silk industry, particularly weavers, will be put to great hardship.

In the interests of growers, consumers and weavers, the silk industry should be rationalized to such an extent that the industry will be able to provide not only employment, but also help in the economic development of the country.

My friend Mr. Oscar Fernandes was just saying in Kannada, that the silk industry must be re-organized, so that it might develop well. As a consumer I have to tell you this: the silk saree is a must, so far as South Indian ladies are concerned—whether they belong to the middle class, or upper class. I have five daughters. For the first daughter's marriage, I spent Rs. 2,000 on silk sarees. For the last daughter of mine whose marriage I have celebrated recently, I had to spend Rs. 10,000 on silk sarees. But the quality and weight of the sarees costing Rs. 10,000 now are far inferior when compared to the earlier low-priced sarees.

The silk industry has become a gamble in the hands of vested interests. Unfortunately, instead of helping the grower or the consumer, the Government is helping the middlemen, who are making huge profits, at the cost of the other two classes. Lakhs of rupees are amassed by middle men. Unless the middle men are removed and we arrange for cooperatives or some other suitable organization, silk industry cannot be developed well.

In the meantime, Karnataka Government has started what-is-called the Silk Exchange. Instead of helping the silk weavers, the Silk Exhange has begun to compete in the bazar. Furthermore, there is the vested interest of moneyed people. They have managed things in such a way i.e. to see that only they are benefited, and not the grower, consumer or the weavers. These middle men make huge profits. They have virtually begun to gamble with the silk industry—and the Government must be careful about it and see that the silk industry develop on modern lines so that the interest of the growers, the interest of the weavers, the interest of the reelers and lastly the interest of the consumers is safeguarded. They should also see that the middle man somehow or other is removed. Then they should also see that the silk industry is not given in the hands of the politicians. When Mr. Devraj Urs was removed from the Ministry, he become the Chairman of the Silk Board. He had no time to devote for the development of the silk industry. After him, another person from the Ruling Party became the Chairman of the Silk Board. Afterwards, when the Janata Party came

to power, they brought their own man and he become the Chairman of the Silk Board, who is the present Chairman. I am quite sure, if the Silk Board is manned by politicians, it will not do any good to the silk industry and to the people also. Therefore, I appeal to the Government that the silk industry must never be given in the hands of the politicians for serving the national interest. For Heaven's sake, do not bring any politicians in the Silk Board and politics in the silk industry.

I appeal to the Government that, for the good development of the silk industry, a Karnataka man who knows the silk trade very well, silk business very well, should be appointed Chairman of the Silk Board. I again appeal to the Government not to bring any politician on the Silk Board. Our experience shows that wherever these politicians are on the oBards, they have used their position for their personal ends, for their own benefit and not for the development of the industry and the good of the people. Therefore, whatever may be the plea of the other hon. members about the silk industry, I strongly appeal to the Government not to bring any politician in the silk industry.

There is a lot of scope for development of the silk industry. In Tamilnadu, they have started the production of raw-silk. Likewise, it should be developed in Andhra Pradesh. in Bihar, in Assam and in many other places in the country where the conditions are favourable for the growth of the mulberry.

The World Bank has given a large fund to the Government. I appeal to the Government to see that the silk industry should be developed on modern and scientific lines so that it considered as a national industry having national outlook. I once again appeal to the hon. Minister and the Central Government to see that there is no party politics, as far as the silk industry is concerned. It should be developed in a scientific way so that we may get the maximise advantage out of it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Oscar Fernandes.

SHRI OSCAR FERNANDES: I seek your permission to speak in Kannada.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

*SHRI OSCAR FERNANDES (Udipi): Mr. Speaker, I come from Karnataka, the birth place of the silk industry. Mysore, the premier city of the State, is synonmous with silk. Recently there had been a problem because of the danger of the flies which infested mulberry plants.

It is not a matter of happiness that we had to import silk from China for meeting our requirements.

I am grateful to the Government for having shifted the headquarters of the Silk Board from Bombay to Bangalore the place where the silk industry has been developing fast. The move will help research for the development of the industry and also the silk growers and users of silk yarn.

The Karnataka Government has received a loan/assistance of Rs. 80 crores from the World Bank for the development of the silk industry and the State Government are doing their best to modernise the industry. The development of the industry will go a long way towards solving the problem of unemployment in our country.

My hon. friend Shri Zain-ul-Basheer mentioned the fact that the Karnataka Silk growers earned about Rs. 10,000 on one acre of cultivation whereas the growers in Maharashtra got about Rs. 500. I would like to say that if the Maharashtra and Assam growers also worked on scientific lines as the

*The original speech was delivered in Kannada.

[Shri Oscar Fernandes]

Karnataka growers they could increase their income to the level of Karnataka silk growers. If scientific cultivation is undertaken we should be in a position to export silk instead of importing it. If the Central Government helped this industry to develop properly and also ensured remunerative prices for the growers, the industry would benefit as would the common man and the country.

The workers of the Central Board are facing certain problems because of the lack of any specific recruitment and service rules the field workers are treated as casual labourers. Government should look into the matter so that the workers can give their best. Another problem which the Board is likely to face in spite of the shifting of its headquarters to Bangalore is the shortage of field staff which is particularly, acute in my constituency, South Canara. A similar shortage of field staff is in evidence in the States of Assam, Madhya Pradesh, Tamilnadu and others. It must be removed for the better functioning of the Board.

If the money spent on the import of silk could be diverted to research we should be able to increase the production in our country to an extent which would deliver us from the necessity to import. The fly which infest mulberry leaves should be dealt with first of all. A stable market mechanism should be established so that the fluctuations in the price of silk are minimised. We must also ensure the payment of remunerative prices to the growers as we do in the case of other agricultural commodities like cotton. If that is not done, the growers may switch over to other commodities.

I think that it is best to leave the selection of Chairman of the Central Silk Board to the Government. We should trust the Central Government to choose a suitable person for the post. The State to which the Chairman belongs should not cause any worry; what is important is whether he is a fit person to hold the post, having the background and expertise needed for the job.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, रेशम उद्योग के विकास के लिये 6ठी पंच वर्षीय यजोना में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है और इस बात का उल्लेख उस योजना के हिन्दी संस्करण के 173वें पृष्ठ पर है। इस समय चार प्रकार का रेशम हमारे देश में पैदा होता है—शहतूत, टसर, एरी, मोंगा । ये प्राय: देश के सभी राज्यों में, खास कर कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, प्राय: सभी जगहों पर, परन्तु इन राज्यों में विशेष रूप से, रेशम की पैदावार होती है । बिहार का भागलपुर सिल्क के लिए बहुत मशहूर स्थान है । वाराणासी और बैंगलोर में साड़ियां और दूसरे वस्त्र बहुत ही अच्छे किस्म के मिलते हैं . . .

एक माननीय सदस्य : लुंगी ।

श्री रामावतार शास्त्री : लुंगी से लेकर कंचुकी तक ।

15.58 hrs.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

हमारे मुल्क में सब से ज्यादा रेशम शहतूत का रेशम होता है, 80 प्रतिशत उस की पैदावार देश में है और आप की छठी पंच वर्षीय योजना में भी कहा गया है—"शहतूत के अतिरिक्त अन्य किस्म के रेशम उद्योग के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है"। यह सरकार की योजना कह रही है । इस का यह अर्थ हुआ कि अन्य प्रकार के रेशम के विकास की तरफ सरकार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाना चाहिये, लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि शहतूत के रेशम के विकास पर कम ध्यान दिया जाय। इस समय हमारे यहां जो रेशम पैदा होता है—1979-80 में 48 लाख किलोग्राम

पैदा हुआ और 6ठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 90 लाख किलोग्राम हो जाने की आशा की जाती है । ठीक इसी तरह से निर्यात भी ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि हमको विदेशी मुद्रा मिल सके । इस लिये उसको 49 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये तक ले जाना चाहते हैं—छठी पंचवर्षीय योजना में । इस समय इस उद्योग में लगभग 16 लाख लोग काम करते हैं आप इनको बढ़ा कर साढ़े इक्कीस लाख तक ले जाना चाहते हैं । तो यह कैसे होगा। इस के लिये यह आवश्यक है कि अनुसंधान का काम रेशम के कीड़ों के सिलसिले में किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस को विकसित कर के सब जगहों पर इसकी पैदावार को बढ़ाया जाए । जितने स्थानों पर हमारे मुल्क में रेशम होता है, वहां पर इस की पैदावार को बढ़ाया जाए लेकिन दुःख की बात है कि खुद बनारस में 5 हजार करघे बेकार पड़े हैं ।

16 hrs.

श्री जैनुल बशर : 5 लाख करघे बेकार पड़े हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो मैं बहुत कम कह रहा था। हमारे भागलपुर में भी हजारों करघे बेकार हैं और हर स्थान पर जहां रेशम की पैदावार होती है, वहां पर करघे बेकार हैं । आप को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि रेशम के धागे उनको मुनासिब दाम पर मिलें क्योंकि इसमें भी मुनाफाखोरी चलती है जैसी हमारे सूती करघों के व्यापार में गड़बड़ चल रही है । मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि जो लोग रेशम का उत्पादन करते हैं, उनको कच्चे रेशम का अगर आप मुनासिब दाम नहीं दिलवाएंगे, उन के सामान को आप खरीदेंगे नहीं, तो धागे बन कर तैयार हो जाएंगे और उनके खपत की व्यवस्था नहीं होगी । बनारस, बंगलौर, भागलपुर आदि जो प्रमुख केन्द्र हैं, उनको अगर आप अच्छे किस्म का रेशम नहीं देंगे, तो हमारे देश का नाम जो कपड़ों के मामले में है, साड़ियों के मामले में है, यहां पर मटका, मूंगा, एरी और टसर जो इतनी अच्छी होती है, और ये नहीं बन पाएंगे, तो हमारे देश की बदनामी होगी ।

अगर आप सचमुच में बोर्ड के जरिए इस को विकसित करना चाहते हैं, तो बोर्ड का मतलब यह होता है कि वह इस बात को देखे कि जो रेशम उपजाने वाले हैं, उनको मुनासिब दाम मिले, इस उद्योग में 16 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और उनके परिवारों के करोड़ों लोग इस व्यवसाय पर जिन्दा हैं । तो मजदूरों की स्थिति कैसी है, यह भी आप को देखना होगा । मजदूरों को ट्रेड यूनियन कानूनों के मुताबिक तन्ख्वाह मिले और अगर नहीं मिलती है, तो ऐसे कानूनों को वहां पर लागू करवाइए ताकि यह न हो सके कि उन का शोषण बड़े पैमाने पर किया जाए । श्रम मंत्री जी भागलपुर से आते हैं । वह उन का क्षेत्र है और वे जानते हैं कि मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। उन की यूनियनें हैं, उन के संगठन हैं लेकिन उन की कोई सुनता ही नहीं ।

एक माननीय सदस्य : संगठन नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : भागलपुर में तो है । और जगहों के लिए आप सही हो सकते हैं । अगर यूनियनें और संगठन नहीं हैं, तो वे बनने चाहिए ताकि मजदूरों का शोषण न हो । एक तरफ आप उत्पादक-कर्त्ता को अधिक दाम दीजिए और दूसरी तरफ जो कपड़ा बनाने वाले मजदूर हैं, उन को ठीक से मजदूरी दीजिए । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कि इस व्यवसाय का, इस उद्योग का विकास नहीं हो सकेगा । इस उद्योग का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है । इसलिये इस बात को दिमाग में रख कर इस की उज्जवलता के लिए अगर आप उचित कदम नहीं उठाएंगे, तो जाहिर बात है कि यह उद्योग उन्नति नहीं कर सकेगा ।

एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड जो है, उस को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए । जो लोग सचमुच में इस उद्योग को विकसित करने में दिलचस्पी रखें, ऐसे लोगों को ही इस का अध्यक्ष बनाइए । अभी तो जिस के लिए मन बन जाता है, अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। पब्लिक सैक्टर में हम देखते हैं कि जो

[श्री रामावतार शास्त्री]

पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं, उन में उन लोगों को, जिन की पब्लिक सैक्टर की फिलोसफी नहीं है, चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर आदि बना दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि वे उद्योग घाटे पर चल रहे हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : वेस्ट बंगाल में क्या किसी कांग्रेसी को आप को सरकार ने किसी अन्डरटेकिंग का चेयरमैन बनाया है ?

सभापति महोदय : शास्त्री जी क्या आप इंल्ड कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं नहीं । मैं यह कह रहा था कि इस बोर्ड का चेयरमैन सचमुच में ऐसा हो जो इस उद्योग के विकास में दिलचस्पी रखता हो और इसका जानकार हो । नहीं तो आप राजनीतिक स्तर पर किसी को बहाल करेंगे तो इसका विकास नहीं होगा ।

जैसा कि हमने इसके बारे में संशोधन दिया है जिस पर कि हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन अगर चेयरमैन को हटाने की जरूरत पड़े तो कारण जरूर बताइये । बिना कारण के किसी को मत हटाइये । अगर जब चाहेंगे तब आप हटा देंगे तो इस उद्योग को नुकसान होगा । इसी तरह से अगर किसी चेयरमैन की अवधि को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उसकी अवधि बढ़ाते समय यह चीज ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उसका काम संतोषजनक रहा है या नहीं । इस उद्योग के विकास के लिए चेयरमैन की कालावधि बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं ।

आप इन दो बातों को ध्यान में रखें । अगर आपने ठीक तरीके से काम किया तो हम सभी चाहते हैं कि इस उद्योग की वृद्धि हो, उत्पादकों को मुनाफा हो और जो मजदूर इस में काम करते हैं, जिन पर कि यह उद्योग निर्भर है उनकी रोजी-रोटी ठीक से चले और उनको वाजिब तनख्वाह मिले । अगर इन सब बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो इस बोर्ड से आप लाभ उठा सकेंगे।

वैसे यह जो बिल बनाया गया है यह कंट्रोवर्सियल नहीं है लेकिन इन बातों की तरफ सरकार को जरूर ध्यान रखना चाहिये।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेशम की बहुत सी किस्में हैं । मूंगा, टसर, मालवरी और एरी इत्यादि । अगर सारे हिन्दुस्तान का जायजा लिया जाए तो सब से ज्यादा टसर की पैदावार बिहार में है और मूंगा 100 फीसदी असम में होता है । और मालवरी 50 फीसदी बैंगलौर कर्नाटक में होती है । वैसे तो थोड़ा-बहुत रेशम और जगहों में भी होता है मगर ये तीन जगहें ऐसी हैं जहां यह सब से ज्यादा होता है । मगर अफसोस की बात है कि हमारे सिल्क बोर्ड के क्षेत्रीय केन्द्र कश्मीर, बम्बई, बैंगलौर, कलकत्ता और मद्रास में है। जहां बिहार में 80 फीसदी टसर होता है वहां इसका कोई सेन्टर नहीं है । इसी तरह 100 फीसदी मूंगा असम में होता है लेकिन वहां भी कोई क्षेत्रिय केन्द्र नहीं है । कलकत्ता में जो क्षेत्रीय केन्द्र है उसके साथ यू.पी., बिहार, असम, नागालेण्ड और सिक्किम इत्यादि को शामिल कर दिया है । जरूरत इस बात की थी कि जहां 80 प्रतिशत टसर पैदा होता है, वहां सेन्टर होना चाहिए था । इस लिए असम में भी इसका सेन्टर होना चाहिए । अफसोस की बात है कि सिल्क बोर्ड का केन्द्रीय सेन्टर बैंगलौर में है लेकिन इन जगहों पर क्षेत्रीय केन्द्र भी नहीं है । इस सदन को यह देखना है कि पैदावार के लिहाज से जहां सब से ज्यादा टसर होता है वहां पर कम से कम क्षेत्रीय सेन्टर होने चाहिएं । पहले नम्बर पर असम में होता है और दूसरे नम्बर पर बिहार में होता है और तीसरे नम्बर पर बैंगलौर में होता है। लेकिन बैंगलौर में तो है और बिहार और असम को नजरअन्दाज कर दिया गया है । इनको नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए ।

बम्बई एक्सपोर्ट के लिहाज से बहुत बेहतर है । इसलिए बंगलौर केन्द्रीय सेन्टर के मैरिट में नहीं आता---न पैदावार में और न एक्सपोर्ट में, लेकिन बैंगलौर के लिए पैरवी हुई, क्योंकि नुमाइंदगी बंगलौर की

ज्यादा है । केन्द्रीय सेन्टर को लेकर मौजूदा चेयरमैन किसी को आसाम भेज रहे हैं, किसी अधिकारी को गोहाटी भेज रहे हैं, लिहाजा ये कि परेशान किया जा रहा है । यह सब नहीं होना चाहिए । हम तो कहेंगे कि एक्सपोर्ट के लिहाज से बांबे दुरुस्त है और पैदावार के लिहाज से आसाम ठीक है और बंबई और बैंगलौर की लड़ाई के बीच सारी बातों को छोड़ कर इसको दिल्ली में रख दिया जाए ताकि किसी को किसी तरह की आपत्ति नहीं हो ।

बिहार पैदावार ज्यादा करता है, फिर भी बिहार में कोई क्षेत्रीय आफिस नहीं खोला गया है, यह अफ्सोसनाक बात है । इसलिए बिहार में और आसाम में क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए। सेंट्रल आफिस सारे झगड़ों को बलाएताक रख कर दिल्ली में होना चाहिए ।

अभी रामावतार शास्त्री जी कह रहे थे कि मजदूरों को यह मिलना चाहिए, वह मिलना चाहिये, मगर मैं कहता हूं कि असल चीज के बारे में उन्होंने तवज्जह नहीं दिलाई है । आज चाइना से सिल्क आ रहा है और यहां के सिल्क से उसकी बनावट अच्छी है और 1/4 किफायत भी मिलती है । फिर कपड़ा बुनने वाला क्यों दूसरा सिल्क लेगा । मैंने नागपुर में यह प्रस्ताव रखा था कि इंपोर्ट बंद किया जाए । चाइना की यह एक पालिसी है कि वह किफायती दामों पर सिल्क एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे हमारे यहां सिल्क का उत्पादन घट जाएगा और यहां का मजदूर भी बेकार हो जाएगा ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं पार्लियामेंट की तरफ से सिल्क बोर्ड में मेंबर हूं। मैं जब वहां पर सूरतें देखता हूं तो पाता हूं कि बोर्ड में मजदूरों की नुमाइंदगी नहीं है । और सिल्क पैदा करने वालों की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि बड़े-बड़े एक्सपोर्टर लोग उसके नुमाइंदे हैं और यही वजह है कि बिहार और आसाम सिल्क के मामले में तरक्की नहीं कर रहा है और न उनको किसी किस्म की रियायतें मिल रही है । मैं चाहूंगा कि सिल्क पैदा करने वालों की नुमाइंदगी इसमें होनी चाहिए ।

इसके अलावा मैं एक चीज की तरफ आप के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाहे आसाम सिल्क पैदा करता हो, चाहे बिहार या बंगलौर पैदा करता हो या कोई भी प्रदेश पैदा करता हो, लेकिन कपड़ा तैयार करने वाले बनारस और भागलपुर के हैं लेकिन बनारस और भागलपुर की ओर से बड़े-बड़े साहूकारों की नुमाइंदगी है, कपड़ा तैयार करने वाले बुनकरों की नुमाइंदगी नहीं है । आपको ताज्जुब होगा कि कपड़ा तैयार करने में भागलपुर और बनारस 80 फीसदी सिल्क तैयार करते हैं । जहां 80 फीसदी सिल्क कपड़ा तैयार होता हो वहां की नुमाइंदगी बोर्ड में न हो, यह बहुत अफ्सोसनाक बात है । मेरी तज्वीज है कि बुनकरों की भी उस में नुमाइंदगी होनी चाहिये ।

1951-52 में सिल्क बोर्ड कायम हुआ था । लेकिन आज तक इसका जो चेयरमैन होता आ रहा है वह दक्षिण भारत से बनता रहा है जहां कम पैदावार होती है, मतलब यह कि साउथ से ही बनता रहा है । आप देखें कि टस्सर बिहार में पैदा होती है, मूंगा सौ फीसदी आसाम में पैदा होता है, मलबरी बंगलौर में पैदा होती है । टस्सर अस्सी परसेंट बिहार में होती है । इतने साल हो गए हैं लेकिन एक बार भी चेयरमेन नार्थ का नहीं हुआ है, यही वजह है कि आज बिहार और आसाम आगे बढ़ नहीं पाया है । आप क्षेत्रीय कार्यालय जैसे बम्बई, बंगलौर, मद्रास में खोलते हैं इसी तरह से आसाम, बिहार वगैरह में भी खोलें । साथ ही चेयरमेन जिस को सरकार नामजद करती है और जिस का चुनाव नहीं होता है, किसी ऐसे इलाके से उसको नामजद किया जाए जो पसमांदा हो, बिहार से करें, आसाम से करें, या काश्मीर से करें, कहीं से भी करें लेकिन वह उत्तर भारत का होना चाहिये, दक्षिण भारत का नहीं । जो मौजूद चेयरमैन है उनकी मुद्दत करीब करीब खत्म हो चुकी है । दूसरा चेयरमैन नार्थ से होना चाहिये साउथ का चेयरमैन करीब तीस साल तक रह चुका है । अब तो कम से कम नार्थ का चेयरमैन होना चाहिए ।

[श्री समीनुद्दीन]

मैं इस सिल्क बोर्ड (संशोधन) बिल की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने सरकार के सामने रखी हैं उन पर गौर किया जायेगा और उनको अमली-जामा पहनाया जाएगा ।

شری سمین الدین (گوڈا) : ادیادھیکش مہودے - ریشم کی بہت سی قسمیں ہیں - مونگا، مالوری اور ابری - اگر سارے ہندوستان کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ تسر کی پیداوار بہار میں ہے اور مونگا ۱۰۰ فیصدی آسام میں ہوتا ہے - مالوری ۵۰ فیصدی بینگلور کرناٹک میں ہوتا ہے - مگر یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے - مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سلک بورڈ کے چھیتریہ مرکز کشمیر بمبئی بنگلور کلکتہ اور مدراس میں ہے - جہاں بہار میں ۸۰ فیصدی تسر ہوتا ہے وہاں اس کا کوئی سینٹر نہیں ہے - اسی طرح ۱۰۰ فیصدی مونگا آسام میں ہوتا ہے - لیکن وہاں بھی کوئی چھیتریہ مرکز نہیں ہے - کلکتہ میں جو چھیتریہ مرکز ہے اس کے ساتھ یو - پی - بہار آسام ناگالینڈ اور سکم وغیرہ کو شامل کر دیا ہے - ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ۸۰ پرسینٹ تسر پیدا ہوتا ہے وہاں سینٹر ہونا چاہئے آسام میں بھی اس کا سینٹر ہونا چاہئے - افسوس کی بات ہے کہ سلک بورڈ کا کھیتریہ سینٹر بنگلور میں ہے لیکن ان جگہوں جہاں یہ کھیتر ہو نہیں ہے - اس سدن کو یہ دیکھنا ہے کہ پیداوار کے لحاظ سے جہاں سب سے زیادہ تسر ہوتا ہے وہاں پر کم از کم چھیتریہ سینٹر ہونے چاہئیں - پہلے نمبر پر آسام میں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر بہار میں ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر بینگلور میں ہوتا ہے - لیکن بینگلور میں تو ہے اور بہار اور آسام کو نظر انداز کر دیا گیا ہے - ان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے -

بمبئی ایکسپورٹ کے لحاظ سے بہت بہتر ہے - اس لئے بینگلور کھیتریہ سینٹر کے میرٹ میں نہیں آتا - نہ پیداوار میں اور نہ ایکسپورٹ میں لیکن بنگلور کے لئے بھاری ہوتی ہے کیونکہ نمائندگی بنگلور کی زیادہ ہے - کھیتریہ سینٹر کو لے کر موجودہ چیئرمین کو آسام بھیج رہے ہیں - کسی ادھیکاری کو گوہاٹی بھیج رہے ہیں - لہذا یہ کہ پریشان کیا جا رہا ہے - یہ سب نہیں ہونا چاہئے ہم تو کہیں گے کہ ایکسپورٹ کے لحاظ سے بھلے آسام کی لڑائی کے بیچ ساری باتوں کو چھوڑ کر اس کو دلی میں رکھ دیا جائے - تاکہ کسی کو کسی طرح کی آپتی نہیں ہو -

بہار پیداوار زیادہ کرتا ہے - پھر بھی بہار میں کوئی چھیتریہ آفس نہیں کھولا گیا ہے - یہ افسوس ناک بات ہے - اس لئے بہار میں اور آسام میں چھیتریہ کاریالیہ ہونے چاہئیں - سینٹرل آفس سارے چھیتروں کو برابر طاق رکھ کر دلی میں ہونا چاہئے -

ابھی رام اوتار شاستری جی کہہ رہے تھے کہ بنکروں کو یہ ملنا چاہئے وہ ملنا چاہئے مگر میں کہتا ہوں کہ اصل چیز کے بارے میں انہوں نے توجہ نہیں دلائی - آج چائنا سے سلک آ رہا ہے اور یہاں کے سلک سے اس کی بناوٹ اچھی ہے اور ۱/۴ کفایتی بھی ملتا ہے - پھر کپڑا بننے والا کیوں دوسرا سلک لیگا - میں نے ناگپور میں یہ پرستاو رکھا تھا کہ امپورٹ بند کیا جائے - چائنا کی یہ ایک پالیسی ہے کہ وہ کفایتی داموں پر سلک ایکسپورٹ کر رہا ہے جس سے ہمارے یہاں کا اتپادن گھٹ جائیگا اور یہاں کا مزدور بیکار ہو جائیگا -

دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا کہ میں پارلیامینٹ کی طرف سے سلک بورڈ میں ممبر ہوں - میں جب وہاں پر صورتیں دیکھتا ہوں تو پاتا ہوں کہ بورڈ میں مزدوروں کی نمائندگی نہیں ہے - اور سلک پیدا کرنے والوں کی نمائندگی نہیں ہے -

بلکہ بڑے بڑے ایکسپورٹر لوگ اس کے نمائندے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہار اور آسام سلک معاملے میں ترقی نہیں کر رہا ہے اور نہ ان کو کسی قسم کی رعایتیں مل رہی ہیں - میں چاہوں گا کہ سلک پیدا کرنے والوں کی نمائندگی اس میں ہونی چاہئے -

اس کے علاوہ میں ایک چیز کی طرف آپ کے مادھیم سے سدن کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ چاہے آسام سلک پیدا کرتا ہو چاہے بہار یا بنگلور پیدا کرتا ہو یا کوئی بھی پردیش پیدا کرتا ہو لیکن کپڑا تیار کرنے والا بنارس اور بھاگلپور کے ہیں لیکن بنارس اور بھاگلپور کی طرف سے بڑے بڑے ساہوکاروں کی نمائندگی ہے کپڑا تیار کرنے والے بنکروں کی نمائندگی نہیں ہے - آپ کو تعجب ہوگا -

کہ کپڑا تیار کرنے میں بھاگلپور اور بنارس ۸۰ فیصدی سلک تیار کرتے ہیں - جہاں ۸۰ فیصدی سلک کپڑا تیار ہوتا ہو وہاں کی نمائندگی بورڈ میں نہ ہو یہ بہت افسوس ناک بات ہے - میری تجویز ہے کہ بنکروں کی بھی اس میں نمائندگی ہونی چاہئے -

۱۹۵۱-۵۲ میں سلک بورڈ قائم ہوا تھا - لیکن آج تک اس کا جو

چیئرمین ہوتا آ رہا ہے وہ دکشن بھارت سے بنتا رہا ہے جہاں کم پیداوار ہوتی ہے - مطلب یہ کہ ساؤتھ سے ہی بنتا رہا ہے - آپ دیکھیں کہ تسر بہار میں پیدا ہوتی ہے - مونگا سو فیصدی آسام میں پیدا ہوتا ہے مالوری بنگلور میں پیدا ہوتا ہے - تسر اسی پرسینٹ بہار میں ہوتی ہے - اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ایک بار بھی چیئرمین نارتھ کا نہیں ہوا ہے - یہی وجہ ہے کہ آج بہار اور آسام آگے بڑھ نہیں پایا ہے - آپ ڈائریکٹوریٹ کھولنا چاہتے ہیں جیسے بمبئی بنگلور مدراس میں کھولتے ہیں اسی طرح سے آسام بہار وغیرہ میں بھی کھولیں - ساتھ ہی چیئرمین جس کو سرکار نامزد کرتی ہے اور جس کا چناؤ نہیں ہوتا ہے کسی ایسے علاقے سے اس کو نامزد کیا جائے جو پسماندہ ہو بہار سے کریں آسام سے کریں یا کشمیر سے کریں کہیں سے بھی کریں لیکن وہ اتر بھارت کا ہونا چاہئے دکشن بھارت کا نہیں - جو موجود چیئرمین ہیں ان کی مدت قریب قریب ختم ہو چکی ہے - دوسرا چیئرمین نارتھ سے ہونا چاہئے - ساؤتھ کا چیئرمین قریب تیس سال تک رہ چکا ہے - اب تو کم از کم نارتھ چیئرمین ہونا چاہئے -

میں اس سلک بورڈ (سنشودھن) بل کی تائید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے سرکار کے سامنے رکھی ہیں ان پر غور کیا جائے گا اور ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا -

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एमेंडमेंट्स हम रखते हैं क्या डिपार्टमेंट उनको देखता है या जो हम बोलते हैं क्या उनको पढ़ा जाता है, उनको स्टडी किया जाता है ? एमेंडिंग बिल तो आप ला कर रख देते हैं लेकिन क्या इस तरफ भी ध्यान दिया जाता है ? सिल्क बोर्ड एक्ट 1948 में बना । सैंट्रल सिल्क बोर्ड की एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है :

This is the decision of the Board:

> "The Member suggested that the present Central Silk Board Act should be amended to give more powers to play a greater role in the quickening of the pace of development and certain other things."

कामर्स मिनिस्टर भी तथा दूसरे मंत्री भी नए आए हैं। इनको समझने में समय लगेगा । आप 1949 के एक्ट को एमेंड करने जा रहे हैं । चेयरमैन के बारे में आप कहते हैं :

> "The Central Government may terminate the appointment of the Chairman after giving notice for a period of not less than three months."

कौन चेयरमैन बन सकता है ? कोई भी बन सकता है ।

The Chairman is to be appointed by the Central Government. The Board shall constitute of the following Members. The Chairman is to be appointed by the Central Government.

कोई कह रहा है कि नार्थ का चेयरमैन होना चाहिये और कोई कह रहा है कि साउथ का होना चाहिये ।

कोई चेयरमैन बन जाय चाहे राजस्थान का ही हो जहां कि सिल्क पैदा नहीं होती । चैयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन्स होगी, कुछ मालूम नहीं । न एक्ट में है और न रूल्स में है । चेयरमैन को क्यों हटाया जाएगा कोई रीजन्स नहीं दिए हुए हैं । एक सेन्टैंस लिख दिया कि :

"The Central Government may termina.e tht appointment of the Chairman after giving notice for a period of not less than three months."

अगर वह चेयरमैन ईमानदार नहीं है चरित्र का गया गुजरा है बोर्ड को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको 90 दिन का समय क्यों देते हैं आप ? उसको तुरन्त हटाइये। आबजेक्ट्स और रीजन्स में क्या लिखा है ? चेयरमैन को हटाने के लिये 3 महीने का नोटिस दिया जायगा । क्या कामर्स डिपार्टमेंट में ऐसा कानून है ? मेरी समझ में नहीं आया ।

It may terminate the services of a Chairman, after giving a notice for a period of not uless than three months. It means 90 days. Chairman has got wide powers.

तो 90 दिन में तो वह 90 लाख रु. खर्च कर देगा। चेयरमैन को 10,000 रु. तक की पावर्स खुद को है । तो चेयरमैन को किस कारण पर हटायेंगे ? दूसरी क्लाज अमेंड किया है:

"Subject to the proviso of the Act, the term of office of the Member shall be such period as not exceeding three years."

Further it has been stated, "as may be prescribed".

आप एक कानून बनाने जा रहे हैं, डेलीगेशन करने जा रहे हैं । कानून बनायें तो 3 साल से कम मेम्बर की मियाद नहीं होनी चाहिए । तो यह जरूरत क्यों हुई । आप जरा पढ़ें क्या लिखा है :

"Except as provided in sub-rule (2) of Rule 8, every Member of the Board shall hold office for a period of three years from the date of his appointmen:, nomination or election as a Member of the board, under section 4(3) of the Act."

आपने पहले ही रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया 3 साल की मियाद । फिर एक्ट में क्यों लाये ? एक्ट को पढ़िये, क्या जरूरत है इन चीजों को लाने के लिये?

Subject to the proviso of the Act, the term of office of the Member shall be such period as not exceeding 3 years. It is already provided in the rules. The rules are in force.

आपके रूल्स प्रोमल्गेट होने के बाद फोर्स में आ गये और रूल्स 1955 में प्रोमल्गेट हुए और आज अमेंडमेंट आ रहा है मेम्बर की मियाद 3 साल होगी। तो यह रूल्स क्यों बनाये गये?

Not exceeding three years, as may be prescribed. Already, it has been prescribed under certain rules. Rules have already been framed and they have been published. They are statutory rules.

तीसरे आपने अमेंडमेंट किया :

"It shall come into force on such date as the Central Government may notify in the official gazette."

ला डिपार्टमेंट क्या देखता है? जब आलरेडी यह एक्ट फोर्स में है 1948 से...

(व्यवधान)

They have already framed the rules. They say, "as prescribed". They have already prescribed. It has already come into force.

कमेटी आन सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन ने मेरे ख्याल से दूसरी लोक-सभा में यह बात कही थी कि हरेक बिल जो एक्ट बन चुके

[श्री मूलचन्द डागा]

हैं, उनमें आप इस प्रकार का संशोधन कर दें, लेकिन आज 20, 25 साल के बाद ये अमेंडमेंट यहां लाये हैं । मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों आवश्यकता पड़ी । एक कारण तो चेयरमैन को हटाने का था लेकिन इसमें यह कोई प्रावीजन नहीं है कि चेयरमैन कौन बनेगा, कैसे बनेगा । चेयरमैन टर्मिनेट कर दिया जायेगा, लेकिन क्यों किया जायेगा, यह कुछ पता नहीं है ।

मेरा कहना यह है कि जो कुछ आपने बिल बनाना है, सोच समझकर बनाना चाहिये, उसमें पावर्स के बारे में होना चाहिये, मेम्बर्स की क्वालीफिकेशन के बारे में होना चाहिये । इसके बोर्ड में लेबर का भी कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है । जो बेचारा सिल्क बनाता है, जो तैयारी करता है, उसका कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, लेकिन कुछ अफसरों की जमात की जमात हो गई है और साथ ही लोक-सभा के 4 सदस्य और राज्य-सभा के दो सदस्य इसमें आ गये हैं और एक कर्नाटक का आ गया है ।

इसमें 66 लाख रुपये एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है, यह बोर्ड आफ पैराडाइज है, जहां चेयरमैन को काम कम करना है और आराम ज्यादा करना है । इसमें यह भी नहीं है कि इसकी एनुअल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी ताकि लोग जांच सकें कि पैसे का किस प्रकार उपयोग होता है । इस सारे एक्ट में यह प्रावीजन नहीं है कि हर साल आडिटेड रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी । सरकार जो एक्ट बनाती है, उसे सारी बातें देखनी चाहियें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है, वस्तुतः मंत्री जी ने इसे अपना उल्लू सीधा करने के लिये यहां पर रखा है । जहां तक इस उद्योग के विकास का सवाल है, उस दिशा में मंत्री जी ने कोई संशोधन का प्रावधान नहीं किया है । मंत्री जी चाहते हैं कि सारी ताकत इनके हाथ में आ जाये, केन्द्रीभूत कर रहे हैं । उद्योग को अपनी मुट्ठी में लाने के लिये अध्यक्ष को हटाया जाये, किस को लाया जाये, कौन जी-हुजरी में रहेगा, यह बात इसमें मुख्य है।

इन्होंने यह नहीं सोचा कि रेशम उद्योग कृषि पर आधारित श्रम प्रधान कुटीर उद्योग है जिसमें 35 लाख लोग काम कर रहे हैं, यह अल्पकालिक या पूर्णकालिक रोजगार पा रहे हैं लेकिन इसमें 10 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग काम कर रहे हैं । इतने बड़े पैमाने पर यह उद्योग चल रहा है, इसका वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार विकास किया जाये, इस दिशा में कोई चिन्तन इन्होंने नहीं किया है । इस इंडस्ट्री के विकास तथा प्रगति की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। उन्हें तो केवल इस बात की चिन्ता है कि जो कुछ करें, अध्यक्ष करें, जब चाहें किसी को अध्यक्ष बना दें और जब चाहें तीन महीने का नोटिस दे कर उसको हटा दें ।

उस ओर न जा कर इस उद्योग के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि रेशम उद्योग भारत का बहुत प्राचीन उद्योग है । ईसा की दूसरी शताब्दी में भारत में बंगाल काफी मात्रा में रेशम निर्यात करता था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी उसका काफी निर्यात हुआ । इस समय भी हमारे देश में जो रेशम पैदा होता है, वह बहुत अच्छी किस्म का है । भारत को यह सौभाग्य प्राप्त है कि प्राकृतिक रेशम के चारों प्रकार--शहतूत, एरी, टसर और मूंगा--भारत में है । जहां तक शहतूत के उत्पादन का सवाल है, भारत का विश्व में पांचवां स्थान है, टसर में दूसरा स्थान है और मूगा के सम्बन्ध में भारत को एकाधिकार प्राप्त है । अगर भारत सरकार इस उद्योग में अभिरूचि ले, श्रम-प्रधान उद्यमियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे, अनुसंधान की व्यवस्था करे और अन्य प्रकार की अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करे, तो यह देश के लिए बहुत लाभदायक होगा ।

देश में रेशम का उत्पादन 30 लाख किलोग्राम प्रति-वर्ष है, जिससे 50 करोड़ रुपये की आय होती है । अगर इस उद्योग को बढ़ाया जाए, तो 100 करोड़ रुपये के उत्पादन की सम्भावना हो जाती

है । इस उद्योग के विस्तार की काफी गुंजाइश है। सारे देश में इसके लायक वातावरण है। बिहार, कर्नाटक, बंगाल, आसाम और मणिपुर आदि सब जगहों में इसका अधिक से अधिक विस्तार किया जा सकता है । रांची में रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र है ,जो कि उत्तर भारत का एक ही केन्द्र है, मगर वहां पर जो काम होना चाहिए, उसका अभाव है ।

कई कारणों से कई जगहों में रेशम उद्योग के कारोबार में गिरावट आ गई है । कर्नाटक में 600 सिल्क इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें से 80 परसेंट सिक होने जा रही हैं, क्योंकि वहां से सिल्क का डाइवर्शन दूसरी जगह कर दिया जाता है । इसी तरह से अन्य जगहों में भी इस उद्योग की हालत खराब है । पिछले साल सरकार ने सिल्क उद्यमियों को आश्वासन दिया था कि ढाई लाख किलोग्राम बाहर से इम्पोर्ट किया जाएगा और उनकी आवश्यकता पूरी की जाएगी । लेकिन पता नहीं, उसमें कहां तक प्रगति हुई है । पिछले वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणव मुकर्जी, ने बनारस के सिल्क उद्यमियों की एसोसियेशन को आश्वासन दिया था कि हम इस उद्योग को डूबने नहीं देंगे और उसमें गति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे । लेकिन पता लगा है कि अभी भी उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं । सरकार को इस बारे में शीघ्र पहल करनी चाहिए ।

सैंट्रल सिल्क बोर्ड का कार्यालय बम्बई में हो या किसी अन्य जगह, लेकिन उसको किसी केन्द्रस्थ स्थान पर रखना चाहिए । माननीय सदस्य, श्री समीनुद्दीन, ने कहा है कि 1948 में यह कानून बनाया गया था और तब से आज तक जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वे साउथ के ही रहे हैं, इस लिए उत्तर भारत में सब जगह यह उद्योग गिर रहा है । उनका भी कहना मैं यथार्थ समझता हूं और उसका समर्थन करता हूं ।

जहां तक सिल्क बोर्ड का सम्बन्ध है, इसमें हर वर्ग के लोगों, खास कर इस उद्योग में लगे हुए, को इस बोर्ड में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए । यह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से कोण प्रेरित होकर केवल अपने ही लोगों को अनुचित लाभ उठाने के लिए शामिल कर लें । इसमें श्रमिकों का खासकर आदिवासी हरिजन और जंगलों में निवास करने वाले लोगों का कल्याण इस उद्योग में संभव है, इसलिए इस उद्योग में लगे लोगों का कल्याण होना चाहिए । जिस तरह से कोयला उद्योग में वैलफेयर आर्गेनिजेशन है, लोह उद्योग में है और दूसरे उद्योग में भी है, उसी तरह की वैलफेयर आर्गेनिजेशन सिल्क उद्योग में भी होनी चाहिए । जो श्रमिक भी इस उद्योग में लगे हुए हैं, उनको आधुनिक ट्रेनिग देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । उनके बच्चों को पौष्टिक-आहार, शिक्षा की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की चिन्ता--इन सब दृष्टिकोणों पर भी विचार होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): Mr. Chairman, Sir, I do not want to get into any controversy over the Amendment. When Government has brought it, they will get it passed. So, I would like basically to concentrate on certain problems of Assam.

As many Members have said, Assam produces the rare quality, moga, which is the monopoly of the Assam cultivators, they export almost 80 per cent of it outside the country. The growers are in abundance not only in Assam but also in Meghalaya from which the Deputy Minister of Commerce comes as well as Manipur. But most unfortunately the Silk Board which has been formed to encourage and develop this particular industry which is basically a labour-oriented cottage industry, is not functioning well in our part of the country. It does not matter whether the headquarters are in Bombay or Patna or Calcutta, but if the Ministry keeps an eye and places an efficient person at the right place, then it can function well and develop the industry.

[Shri Santosh Mohan Dev]

In one of the Consultative Committee meetings I drew the attention of the hon. Minister, and I would again draw his attention now, to the question of finance. This is a cottage industry and banks should give finance to the growers, but unfortunately though there are so many cooperatives in this particular trade in Assam, they do not get any help from the nationalised banks. It should be looked into. On certain occasions I have written to the Commerce Ministry giving the names of the banks, but even then no tanglible result has come. These growers are investing either their own money which is very small in quantity or they are getting finance from private persons at high interest. In order to help the growers, there should be an effective Purchase Board so that the growers can get back the money which they invest for growing this.

I had been to China about seven months back and saw their silk industry. They have introduced many types of designs to compete in the world market in moga and other silk products. The Silk Board should come forward to give market intelligence about the different designs which are coming up in the world market in the silk industry, in the moga industry, and to develop these designs in the field in our country by employing experts in the Silk Board, so that they can go and know the marketing intelligence and technical know-how.

Another thing I would say is that in the Silk Board, as many Members have said, there is no representative of the interests of the growers. I do not know whether it is possible to do that. When trade fairs are being held in various parts of the country as well as abroad, the growers who have proved their efficiency of their products should be encouraged to go and participate in that. Unfortunately, the officers go and come back by collecting their products. They exhibit their products there. It is not fair. The growers should go there and they should be encouraged to go there to find out how their products are displayed there and it is only by that they will be able to learn many things.

With these words, I request the hon. Minister to note down the suggestions of mine. He should also implement them and they should remain in cold-storage as is the case in the past.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं सिल्क बोर्ड अमेण्डमेन्ट बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। तथा चन्द सुझाव जो मेरे दिमाग में हैं आप के सामने प्रस्तुत करता हूं। बोर्ड की फार्मेशन के सम्बन्ध में जिस प्रकार की मेम्बरशिप इसमें होनी चाहिए, उस का उल्लेख आप ने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में किया है--

"The Board has members representing various interests associated with the silk industry."

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं--जब आप ने आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में खास तौर से इस बात को कहा है कि वेरियस-इन्टरेस्ट्स को इस में एसोशियेट किया जायेगा, तो अब तक जितने सिल्क बोर्ड बने हैं उन में कौन-कौन से इन्टरेस्ट्स को शामिल किया गया है? जैसा अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, इस में वीवर्स का इन्टरेस्ट शामिल रहता है, क्या वीवर्स का कोई प्रतिनिधि अभि तक इस में शामिल किया गया? इस में मजदूरों का इन्टरेस्ट रहता है, क्या मजदूरों का कोई प्रतिनिधि इस में शामिल किया गया? क्या ग्रोअर्स का कोई प्रतिनिधि इस में शामिल किया गया? यदि इन लोगों को इस में शामिल किया जाता तो जिस प्रकार का शोषण आज हो रहा है, जिस में मिडिलमैन सारा प्राफिट खुद हड़प जाता है, ग्रोअर्स, कन्ज्यूमर्स, लेबर, वीवर्स सब सफर कर रहे हैं, वह न होता। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप जो नया बोर्ड बनायें इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि वह

सब का प्रतिनिधित्व रखने वाला बोर्ड हो जो इस उद्योग से सम्बन्धित सब के इन्टरेस्ट को वाच करेगा।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह बोर्ड इस तरह का होना चाहिये जो इस में काम करने वालों के इन्टरेस्ट को वाच करे। बोर्ड यह देखे कि इस में काम करने वाले मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलती है या नहीं। इस इण्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूर, वीवर्स, ग्रोअर्स, उन को क्या-क्या फैसिलिटि सिल्क बोर्ड की तरफ से इन इण्डस्ट्री को पनपाने के लिये दी जानी चाहिये उन बातों पर यह बोर्ड ध्यान दे तथा उन को वे सुविधायें उपलब्ध करायें। जब तक इस तरह का काम बोर्ड नहीं करेगा, तब तक यह इण्डस्ट्री नहीं पनप सकेगी।

यहां पर यह कहा गया है कि हमारी यह इण्डस्ट्री बहुत पुरानी इण्डस्ट्री है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जह न देने की वजह से यह इण्डस्ट्री खत्म होती जा रही है। दूसरे मुल्क इस दिशा में आज हम से ज्यादा बढ़ रहे हैं। यदि हम ने अभी से इस दिशा में सही कदम न उठाये तो इस से आगे चल कर इस उद्योग को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस में काम करने वाले लोगों को तरह-तरह की सुविधायें, जैसे मैडिकल फैसिलिटी तथा अन्य फैसिलिटीज की तरफ ध्यान दिया जाय। उन की वेलफेयर एक्टिविटीज, उन की एजूकेशन, उन की हैल्थ, रैक्रिएशन तथा अन्य सुविधायें उन को मिलनी चाहियें जिस से उनका विकास हो और यह इण्डस्ट्री आगे बढ़ सके।

बोर्ड के सदस्यों की अवधि आप ने तीन साल रखी है। मेरा यह निवेदन है कि तीन साल की अवधि तो ठीक है, लेकिन अलग-अलग लोगों को इस में शामिल किया जाना चाहिये। जैसे अभी बताया गया कि देश में बहुत से राज्य इस उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं उन सारी स्टेट्स के रिप्रेजेन्टेज को, चाहे वीवर्स हों, मजदूर हों, एक्सपर्ट्स हों, जितने भी इन्टरेस्ट्स इस में शामिल किये जा सकते हैं उन को यहां पर लेना चाहिये, खास तौर से जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है उन को इस में शामिल करना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो यह बोर्ड ज्यादा अच्छी तरह से चल पायेगा और इस इण्डस्ट्री के पनपाने में ज्यादा योगदान देगा।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि एक दफा मेम्बर बन जाने के बाद तीन साल के बाद उन्हीं मेम्बरों को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। उन के स्थान पर नये लोगों को चान्स दिया जाना चाहिए, जिस से वे और ज्यादा मुस्तैदी से इस बोर्ड की एक्टिविटीज को बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अगला मेरा सुझाव चैयरमेन के सम्बन्ध में है। चैयरमेन के लिए आप ने जो यह प्रावधान किया है, कि उस को हटाने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा, यह ठीक नहीं है। जैसा हमारे डागा जी ने कहा कि किसी मजदूर को हटाने के लिए, किसी अधिकारी को हटाने के लिए आप एक महीने का नोटिस देते हैं, तो चैयरमेन को हटाने के लिए आप ने तीन महीने के नोटिस का प्रावधान क्यों किया है। तीन महीने का समय बहुत ज्यादा होता है। किसी चैयरमैन पर सरकार का विश्वास नहीं है, तो उस को इतना लम्बा समय देने की आवश्यकता नहीं है। उस को तुरन्त हटाना चाहिए और अगर आप कानून की खानापूरी ही करना चाहते हैं, तो उस को एक महीने का नोटिस दिया जाना काफी है। इसलिए मेरा कहना यह है है। कि 3 महीने का जो समय आपने रखा है, वह बहुत ज्यादा है।

अलग मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई चैयरमेन खुद पदमुक्त होना चाहता है, तो उस के लिए भी तीन महीने का समय आपने रखा है। यह बहुत ज्यादा है। कोई आदमी रहना नहीं चाहता तो वह अनमने मन से काम करेगा और उसको आप तीन महीने का और समय देंगे। इस से इंडस्ट्री खराब होगी और बोर्ड की जो एक्टिविटीज हैं, उन में सुस्ती छा जाएगी और वह कोई काम नहीं करेगा। इसलिए यह जो तीन महीने समय रखा है, इस को भी एक महीना किया जाए। ये मेरे सुझाव हैं, जिन पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, ऐसा मैं समझता हूं।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to the hon. Members for having supported the Bill and also for having shown great interest in the development of silk industry in the country.

Sir, although the amendment confines to a limited issue of laying down a procedure for the removal of a Chairman yet in the course of the debate the hon. Members have pratically covered all the aspects ; ertaining to silk industry. I do not propose to deal with all those aspects which have been raised by the hon. Members especially in view of the fact that very soon the House will have another opportunity of discussing it when the Demands for grants pertaining to the Ministry of Commerce will be taken up for discussion in this House. However, since some hon. Members have raised certain important issues, I will try to touch upon a few things. Many hon. Members have said that the production of silk has not come up in the country and it has not progressed so far. I may point out that this particular statement may not be completely correct. In fact, the production of silk in this country has gone up from 900 m. tonnes in 1951 to 5041 m. tonnes in 1981. In the field of exports also whereas in 1951 our export, was to the tune of Rs. 53 lakhs, in 1980-81 it has gone up to Rs. 53 crores. We hopefully expect that our export figure of 1981-82 will be to the tune of Rs. 65 crores.

Then, I must also inform the House that the investment that we have made for the development of sericulture industry has gone up considerably, from the First Five Year Plan to the Sixth Five Year Plan. During the First Five Year Plan our allocation was Rs. 45.97 lakhs and, as the hon. Members are aware for the Sixth Five Year Plan our allocation is Rs. 167.37 crores. Out of this the allocation under the State Plan is Rs. 136.37 crores and under the Central project the allocation is Rs. 31 crores. I am giving this figure so that the hon. Members may bear in mind that the development of sericulture industry or the Silk Industry is the primary responsibility of the States and our function in this industry is to see that the Central Government helps the State Governments and promote and give all sorts of guidance and assistance to the State Governments. I can assure the House that as far as our Ministry is concerned, we shall not be found lacking in our effort to develop this industry.

Now, I will touch upon a few points which have been raised by the hon. Members. Many hon. Members have raised the question as to why this particular amendment to the Act has been brought forward now. Mr. Daga has also raised this question that since the Board was constituted in 1949 under the Act of 1948, which was the necessity of bringing forward this Amendment at this time and not earlier. Sir, the fact is that when this Silk Board was constituted, it was chaired by the Minister in-charge of the Commerce Ministry and the first Chairman was Dr. Shayama Prasad Mukherjee and at one stage we had Pandit Jawaharlal Nehru as the Chairman of the Central Silk Board. After that, this Silk Board was chaired by the Textile Commissioner who is an official within the Ministry. I was only in 1968 that this practice was discontinued and a non-official Chairman was appointed and even now we are having a non-official Chairman. Therefore, the question of removing the Chairman at that time did not arise.

Then, Sir, Mr. Daga has raised a particular point of not prescribing the qualifications for the Chairman In this connection, I would like to clarify as to why there is no prescription of qualifications for the Chairmanship. One thing I want to make clear here is that this is a post which is normally a part-time job and the Chairman is not recruited by the UPSC or any other body. Therefore, the

question of prescribing the qualifications does not arise and when the Chairman is appointed by the Government it is always borne in mind that the person who would be the Chairman of this Board has to be a public man of known eminence and reputation and he has to be a person who should be having a background in silk and sericulture industry. I am mentioning this point because one hon. Member has said that when the Chairman is appointed the Government should see to it that he has got good knowledge in sericulture, interest in sericulture, etc. I think Mr. T. R. Shamanna made this point

16.54 hrs.

[SHRI SOMNATH .. CHATTERJEE—*in the Chair*]

I do agree with the hon. Member and Government will always bear this in mind whenever it appoints a Chairman.

Then there are some Members who have raised the question about the representation of the labour member and a weaver in the Central Silk Board.

May I draw the attention of the hon. Members to Section 4, sub-section (j) of the Central Silk Board Act, which provides that eight persons shall be nominated by the Central Government, of whom one shall represent the spun silk industry, one the silk throwing and twisting industry, one the silk weaving industry, one labour and two of them shall be experts in sericulture. Therefore, the Act already provides for representation of the weavers as also for the labour. One thing should be borne in mind that sericulture and the silk industry is a cottage industry, it is a rural industry. Therefore, it is the village people, the rural people who are themselves engaged in this industry and, therefore, the question of having more labour representation or workers representation in this Board does not arise. It already exists.

The hon. Member, Shri Zainul Basher, gave some production figures of silk in different States and said that Karnataka is not a State which produces the maximum quantity of silk. Now, there are four varieties of commercially known silk, they are categorised mainly into two categories, mulberry and non-mulberry. Shastriji has pointed this out. We produce the maximum quantity of mulberry silk. As far as the non-mulberry silk is concerned, Shri Zainul Basher's contention may be correct. Out of the total production of 5041 metric tonnes of silk during 1980-81, the production of mulberry silk was 4593 metric tonnes, and that of non-mulberry silk 448 metric tonnes only. And out of 4593 metric tonnes of mulberry silk, Karnataka produces 2800 metric tonnes. The argument of the hon. Member was that since Karnataka does not produce much of silk, it is not necessary to shift the headquarters of the Central Silk Board to Bangalore. Many hon. Members have said that the Government is going to shift the headquarters from Bombay to Bangalore. It is not a fact that the Government is going to shift the headquarters from Bombay to Bangalore, but the fact is that it has already been shifted.

Further, some hon. Members have alleged that during the last three months, Silk Board has not been working and nobody has gone to Bangalore. This is not a fact. The Silk Board has been functioning, but there are some employees who are still in Bombay; they have expressed their difficulties to move and we are trying to sort out this problem.

Shastriji and some other hon. Members have mentioned about the problems that the weavers have at Varanasi. We are aware of that. The particular type of yarn that is required at Varanasi is not available at the moment, but as the House is aware, we are importing 250 metric tonnes of silk from China. Some quantity has already arrived, but this

[Shri P. A. Sangma]

particular yarn has not arrived. We hope that by the end of April or early May, this particular consignment will arrive. As and when it arrives, we shall distribute this yarn to the Varanasi weavers, and we hope that their problems can be taken care of to a certain extent.

Hon. Members. Prof. Pal, Shri Sontosh Mohan Dev, and a few other hon. Members mentioned about Assam and north-east region and also added that I come from that region. I would like to assure the hon. Members that the Government of India particularly the Prime Minister herself is paying special attention to the development of the north-east region.

17 hrs.

As far as the Commerce Ministry is concerned, I can assure the Hon. Members that in the matter of silk, handlooms or handicraft or plantations we shall do our best for their development in the North-Eastern region so that they do not lag behind. In fact, last year, 1981-82, we have taken a number of steps in respect of the silk industry. I think it is a long thing. I don't think I will have much time to read out to show what has been done. I think I will inform Shri Dev privately. I will submit to him all the information he wants. I don't want to take time of the House. Otherwise I can read it out. There is no problem.

As far as this particular amendment is concerned as I have said at the very beginning when I was moving the Bill for consideration, it is a small amendment, a minor amendment to correct the lacuna in the existing Act, as it does no prescribe a procedure in the situation when we have to remove the Chairman. It simply gives the procedure. Therefore, I would request all the hon. Members, in view of the support that they have extended, to withdraw their amendments and pass this Amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1982." (5)

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Motion for consideration to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill further to amend the Central Silk Board Act, 1948 be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2—(*Amendment of section 4*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up Clause 2. There are some amendments.

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): Sir, I beg to move:

Page 1,—

after line 16, *insert*—

"Provided that the Chairman is given reasons for his removal" (3)

Page 2, —

after line 5 *insert*—

"Provided that the same Chairman may be appointed for a second term if his work as Chairman is satisfactory." (4)

SHRI SUDHIR KUMAR GIRI (Contai): I beg to move:

Page 1, line 16,—

after "months" *insert*—

and" the opportunity to defend himself against the charges on the basis of which such termination is made;" (8)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 1,—

after line 12, *insert*—

"(5A) No person shall be chosen second time as a Member of the Board".

"(5B) One member shall be elected by the members of the labour unions in the silk industry". (10)

Page 1, line 15,—

after "him" *insert*—

"reasons and" (11)

Page 1, line 16,—

for "three" *substitute* "two" (12)

Page 1,—

after line 16, *insert*—

"Provided that the reason for the removal of the Chairman shall be intimated to him in writing and shall not be other than a technical or professional one." (13)

Page 2, line 2,—

for "three" *substitute* "two[(14)

Page 2,—

after line 5, *insert*—

"Provided that the Chairman may be appointed for a second term if his work as Chairman is found to be satisfactory and deemed necessary for the development of the activities of the Board but no person shall be appointed as Chairman for more than two terms." (15)

श्री रामावतार शास्त्री: मैंने एमैंडमेंट नम्बर 10 में एक धारा जोड़ने के लिए कहा है । यह पंक्ति ग्यारह के बाद है । यह एमेंडमेंट इस प्रकार है:

5 (ख) एक सदस्य रेशम उद्योग में श्रमिक संघों के सदस्य निर्वाचित करेंगे । अभी मंत्री जी ने कहा कि इस बात की व्यवस्था है और मजदूरों के प्रतिनिधि बोर्ड में रखे जाएंगे । यह तो मान लिया । लेकिन उसका निर्वाचन कौन करेगा ? अगर सरकार करेगी तो मैं इसे पसन्द नहीं करता । इसका निर्वाचन उस उद्योग में काम करने वाले मजदूर संघों को करना चाहिये और यही मेरा एमेंडमेंट है । यह नहीं कि ऊपर से थोप दें या आई एन टी यू सी के आदमी को ला कर बिठा दें । यह नहीं होने दिया जाएगा । इसलिये जितनी यूनियनें हैं या संगठन हैं जो इस उद्योग के अन्दर काम करते हैं सब की राय लेनी होगी और जनतांत्रिक प्रणाली के मुताबिक जिनको ज्यादा वोट आयेगा वह चुना जायेगा, किसी को शिकायत नहीं होगी । यही मेरा संशोधन है ।

SHRI SUDHIR GIRI: There is a conflict between the individual and the State, ever since the inception of the State itself. When a very serious conflict goes on, the State must preserve the independence of the individual. If the freedom of the individual cannot be preserved, he cannot perform his duty properly.

How can this independence be secured? For those who are in service, some service conditions must be prescribed, according to which they can perform their duty with dignity and independence. I have brought this amendment with the idea that the independence of the Chairman must not be taken a way by the Government, in order to fulfil their own vested interests.

Nowadays, we find that political patronage is being bestowed on those whom Government blesses. And some occassions may arise when the Government may remove a Chairman, and appoint another, new Chairman in order to bestow some political patronage on somebody.

I do no support the view that the Chairman should remain there, at the cost of efficiency; i.e. if there is an inefficient Chairman he must be kept

[Shri Sudhir Giri]

there I don't support him. But I think no one should be appointed to that post in order to give some political patronage. Natural justice demands that whenever a Chairman is being removed, he should be charged; and he should also be given the chance to defend himself against the charges.

In the amending Bill, there is no such provision, that the officer or the Chairman whom Government is going to remove, will be given any chance to defend himself. So, I have brought this amendment so that whenever the Chairman is removed, or notice of termination of his services is served on him, he will be given a chance to reply.

SHRI P. A. SANGMA: As far as Mr. Ramavatar Shastri's point is concerned, I have already answered it. I have nothing more to say, because the Act itself provides that there will be representation of labour. Therefore, I have drawn your attention to the relevant provisions of the Act. Mr. Giri has spoken about natural justice and said that he should be given an opportunity. The mere fact that we are giving him three months shows that we are not arbitrary. On this side the members have said, why are you giving him three months' notice; it should have been only one month; and we have rejected that amendment—and we are saying that we do not want to be arbitrary and therefore, we are giving him three months' time; three months notice is there. Therefore, the question of taking arbitrary action does not arise; and this is the stand taken by the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I shall put all the amendments moved by the hon. members to the vote of the House.

Amendments Nos 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14 *and* 15 *were put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 2 *was added to the Bill.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Clause 3. There is no amendment. The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 *was added to the Bill.*

Clause 1—(*Short title and commencement*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): I beg to move:

Page 1, line 4,—

for "1981" *substitute* "1982" (2)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

Page 1, line 4,—

for "1981" *substitute* "1982" (2)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, *as amended, was added to the Bill.*

Enacting Formule

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I beg to move:

"For "Thirty-second" *substitute*— "Thirty-third" (1)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"For "Thirty-second" *substitute*— "Thirty-third" (1)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): I beg to move:

"That the Bill as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

17.14 hrs.

MOTION RE. CONTEMPT OF THE HOUSE

MR. DEPUTY-SPEAKER: As the House is aware, at about 12.35 hours today, six visitors calling themselves Keshar Sharma, Bhagat Ram Gupta, Anil, Shyam Lal Garg, Mahabir Singh and Ravinder Pal Singh shouted slogans from the Visiters' Gallery and tried to throw some leaflets on the Floor of the House. The Watch and Ward Officer took them into custody immediately and interrogated them. The visitors have made statements but have not expressed any regret for their action.

I bring this to the notice of the House for such action as it may deem fit.

AN. HON. MEMBER: One year. (*Interruptions*)

ANOTHER HON. MEMBER: One month. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please please.

Mr. P. Venkatasubbaiah.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): I beg to move:

"This House resolves that the persons calling themselves Keshar Sharma, son of Shri Tep Ram Sharma, Bhagat Ram Gupta, son of Shri Ram Kumar Gupta, Anil, son of Shri P. C. Mittal, Shyam Lal Garg, son of Shri Hazari Lal, Mahabir Singh, son of Shri Chandagi Ram and Ravinder Pal Singh, son of Shri P. P. Singh, who shouted slogans at about 12.25 hours today from the Visitors' Gallery and attempted to throw some leaflets from there on the floor of the House and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, have committed a grave offence and are guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that the said Weshar Sharma, Bhagat Ram Gupta, Anil, Shyam Lal Garg, Mahabir Singh and Ravinder Pal Singh be sentenced to simple imprisonment till 6 P.M. on Wednesday, the 24th March, 1982, for the aforesaid contempt of the house and sent to Central Jail, Tihar, New Delhi.

(*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: No, no, no. (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH TYTLER (Delhi Sadar): Mr. Deputy-Speaker, Sir